भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3276

20.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकाइयां और ओडिशा से प्रस्ताव

3276. **श्री मानस रंजन मंगराजः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में शुरू/चालू की गई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकाइयों का ओडिशा सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ओडिशा में ऐसी इकाइयों के स्थान, निवेश, उत्पादन क्षमता और सृजित रोजगार सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओडिशा सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार/मंत्रालय को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण पारितंत्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के संयोजन, बैटरी निर्माण, ऑटो घटक और चार्जिंग अवसंरचना शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा और अनुमोदन/सहायता की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में शुरू/चालू की गई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकाइयों से संबंधित डेटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। भारी उद्योग मंत्रालय, ऑटोमोटिव क्षेत्र (इलेक्ट्रिक वाहनों सहित) में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के उद्योग हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम का कार्यान्वयन करता है। पीएलआई-ऑटो स्कीम के तहत स्थापित विनिर्माण इकाइयों की राज्य-वार सूची निम्नानुसार है:

क्रं.सं.	**राज्य**	**विनिर्माण इकाइयों की संख्या (31.12.2025 के अनुसार)**
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	असम	1
3.	गुजरात	3
4.	झारखंड	1

5.	कर्णाटक	13
6.	मध्य प्रदेश	5
7.	महाराष्ट्र	20
8.	राजस्थान	2
9.	तमिलनाडु	13
10.	तेलंगाना	3
11.	उत्तर प्रदेश	2
12.	उत्तराखंड	4
	कुल	**69**

(ग) और (घ): पीएलआई-ऑटो स्कीम, पीएलआई-एसीसी स्कीम और पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत ओडिशा सरकार से (चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना हेतु) कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

****